THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : That will be considered.

SHRI BHUPESH GUPTA : You will remember—why I am getting up is because—the Minister himself said that he would welcome a discussion in the House. We have also given notice. Notice is not the problem. If you also give a direction from the Chair that time should be found for a discussion on this I think it would be helpful.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The Chair will give no direction at this stage.

THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, I beg to move :

> "That the Bill to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, this is really a very simple piece of legislation. Parliament has already had an opportunity to discuss this threadbare when the Unlawful Activities (Prevention) Act came before the House. At that time our legal advice was that the law will apply to the entire country but subsequently doubts arose whether this would apply to the State of Jammu & Kashmir or not. Though by its very nature the law should apply to the entire country we thought we should put it beyond any shadow of doubt as to whether this law applied to the State of Jammu & Kashmir or not and therefore we are bringing this amending Bill to clarify that this law fully applies to the State of Jammu & Kashmir. A Presidential Order was issued empowering Parliament to legislate for the State of Jammu & Kashmir and it is in pursuance of that Order that we have brought this Bill before the hon. House.

I do not think any clarificatory speech on my part is necessary and I hope the House will wholeheartedly support this measure that we have brought before the House and pass it.

The question was proposed.

श्री जी० बरबोरा (आसाम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेंडमेंट बिल जो अनलाफूल एक्टिविटीज प्रिवेंशन बिल 1967 में बना था, के लिए लाया जा रहा है और इस बिल का मकसद यह है कि सरकार इस ऐक्ट को जम्मू और काश्मीर पर भी लागू करना चाहती है। लेकिन इस ऐक्ट को लागू हुए दो साल हो गये और इस दो साल में देश में कितनी अनलाफूल एक्टिविटीज हुई और उन को सरकार ने कितना रोका इस की कोई जानकारी हम को नहीं है। आज इस देश में सरकार के हाथ में काफी ताकत है और रोज नये नये कानून जनता के अधिकारों को रोकने के लिए वह बनाती है और उन का मकसद सरकार यही बताती है कि उसे अनलाफूल एक्टिविटीज को रोकना है। सरकार के हाथ में प्रिवेंटिव डिटेंशन ऐक्ट है, देश का जो साधारण आईन है उस में भी काफी क्षमता सरकार के हाथ में है और यदि कोई व्यक्ति अन्याय या कोई गैर कानूनी काम करता है, कोई राष्ट्र विरोधी काम करता है तो वह उस को रोक सकती है। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह अनलाफूल एक्टिविटिज प्रिवेंशन ऐक्ट भी देश के कोने कोने में चल रहा है और जगह जगह राष्ट्र विरोधी काम भी चल रहे हैं और उन को रोकने का काम अभी तक हुआ नहीं है। इसी लिए इस कानून को अभी जम्मू काश्मीर तक बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है बल्कि यह अनलाफूल एक्टिविटिज ऐक्ट जो है उस को बिल्कुल रिपील कर देना सही है।

अनलाफुल एक्टीविटिज को जो यह सरकार रोक नहीं पा रही है उसकी कुछ मिसाल मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जैसे की एक रेवरेंड रोचुंगा पुदायते, मणिपुर के हैं माड़ कम्युनिटी के, उन रेवरेंड रोचुंगा पुदायते को करीब आठ-दस साल से अमेरिका का पासपोर्ट दिया हुआ है, वह कभी कभी साल में एकाध महीने के लिये मणिपुर में आते हैं। इंडो-बर्मा पायनियर मिशन से वह सम्बन्धित हैं। उस मिशन का नाम पार्टनरशिप मिशन में बदल दिया गया है और इस पार्टनरशिप मिशन के जरिये देश में क्रिश्चियनिटी के प्रसार के नाम पर, मानव-सेवा के नाम पर कुछ काम वहां चलता है लेकिन ज्यादातर अमेरिकन विदेश-नीति की तरफ से उसका काम हो रहा है

और हिन्दुस्तान का जो राष्ट्रीय स्वार्थ है उसके खिलाफ काम हो रहा है और उस मिशन के जरिये से रेवरेंड रोचुंगा पुदायते के नेतृत्व में वहां कुछ स्मगलिंग वगैरह भी होती है, क्योंकि जो कस्टम्स ड्युटी वगैरह देनी पड़ती है उसको दिये बिना विदेशी सामान लोग ले आते हैं और वह सब सामान वहां लोग बिक्री करते हैं और इस काम में इन लोगों को काफी बड़े बड़े लोगों से मदद मिलती है। जैसे कि वहां ड्युटी फ्री गिफ्ट की डील में फारेन एक्सचेंज इज इनवाल्व्ड। वहां उनको कारोगेटेड आयरन शीट्स को अमेरिका से ले आने का मौका मिला था लेकिन यह शर्त रही थी कि इसको बिक्री नहीं किया जाय परन्तु इस सी० आई० शीट्स को भी इन लोगों ने कोई और मिशन को हैंड-ओवर कर दिया और उसके जरिये से उसका दाम अमेरिकन डालर में अमेरिका में लिया गया और इस डालर के जरिये वह लोग कुछ आर्मस् वगैरह भी ले आते हैं, जो आर्मस् कि वहां लोगों में बेचा जाता है। कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे कि शिलांग हिल के चीफ एग्जीक्युटिव आफिसर हैं, नार्थ कछार हिल्स के भी कुछ ऐसे अफसर नाग हैं और इन लोगों को वह दिया जाता है। इन लोगों को इस काम में, रेवरेंड साहब को इस काम में मणिपुर के जो चीफ कमिश्नर श्री बालेश्वर प्रसाद जी हैं उनका भी समर्थन है, जो कि कुछ दिनों में बर्मा में इंडियन अम्बैसेडर बन कर जाने वाले हैं। शायद बालेश्वर प्रसाद जी का भी उनसे सम्पर्क है और रेवरेंड रोचुंगा पुदायते की तरफ से, उस मिशन के जरिये से उनको, श्री बालेश्वर प्रसाद को, रेफ्रिजरेटर्स, फारेन मेड कैमराज ये सब चीज दी जाती हैं।

इस सब से यही साफ होता है कि देश की सेवा के नाम पर, देश में धर्म प्रचार के नाम पर, गरीबों की सेवा के नाम पर, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस देश के बुनियादी स्वार्थ के खिलाफ काम कर रहे हैं और इन लोगों का प्रोत्साहन इसी सरकार से होता है जिस सरकार के हाथ में इतनी कुछ कानूनी ताकत है और जो सरकार अनलाफुल एक्टीविटिज एक्ट को बनाये बरखती है और उस सरकार के जो बड़े बड़े अफसर हैं उन लोगों का समर्थन भी इन लोगों के पीछे है। यह सरकार रेवरेंड रोचुंगा पुदायते जैसे देश के स्वार्थ के खिलाफ काम करने वाले आदमी के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। ऐसे और भी लोग हैं, खास कर के जो उत्तर पूर्वी सीमान्त इलाका है, आसाम हो, उर्वसियम हो जिसको लोग नेफा कहते हैं, मणिपुर हो, नागा लैंड हो, इस सब इलाके में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि विदेशी राष्ट्रों के स्वार्थ में आज काम कर रहे हैं और वह बड़ी बड़ी जगहों में हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, कोई सरकार का बड़ा अफसर है, कोई युनिवर्सिटी में घुसा हुआ है। यहां मैंने सिर्फ एक मिसाल रखी है लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर जब सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर पाई तो इस एक्ट को अभी काश्मीर की सीमा तक बढाने की कोई जरूरत है ही नहीं बल्कि इस एक्ट को बिल्कुल रिपील कर देना सही है।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, now when the Act is being extended to another State of the Indian Union, namely, the State of Jammu and Kashmir, the very first thing I should like to know is whether there was any proper consultation between the two Governments. I am sure there has been. Otherwise, it would not be proper for the Centre to extend it under the agreement that was arrived at. Now, I am not going to deal with this aspect of the matter. It is a technical thing.

Now, the question of secession, I believe is covered by this Act. Anyone who advocates secession of any part of Indian territory would be liable under this Act, to prosecution. Obviously nobody should advocate secession of any part of India and there need be no two opinions on the subject. The territorial integrity of our country has to be observed and maintained and that is, of course, the paramount duty of the authorities, but the Government is gradually developing an administrative and bureaucratic approach to this problem. I say this because

[Shri Bhupesh Gupta]

it we are to ensure the territorial integrity of the country it is essential that patriotism does not become a mere talking point, but becomes a part and parcel of our life and people are convinced that territorial integrity should be observed and maintained. Now, it would be a mistake to think that everybody who talks about something or other at a given moment is always guided by cool thinking or deliberation. Now, take, for example, the Nagas. The Nagas are a part of India. Not only Nagaland is already functioning as a constituent State of the Republic, but the other part also, which is not yet constitutionally or, in fact covered by that part of Nagaland, is also a part of India. No part of the Naga territory is outside the Indian Union, but the fact remains that some of the Indian citizens feel that they have some grievance and that the grievance can be voiced only by taking this kind of extreme and I say wrong slogan, as has been the case with what are called Naga hostiles. Now, even this word 'hostile', I do not like. If some Indian citizens go wrong, they need not be treated as hostiles, in the sense as if they are hostile to the Republic. Anyway, these expressions are not good expressions in the long run, however administratively they may seem convenient at a given moment. But here again, the solution will ultimately have to be found at the political level. There is no military solution to the problem of national integration when emotion is involved, when you want people to be integrated in their thinking and way of life with the rest of the country, what we need is to create confidence among them. If they have gone in the wrong path, win them back to the right course. That is how we should approach this matter. Obviously the Nagas are not a match, those who are fighting are no match for the might of the Indian Union or the Republic, but the fact remains that it has not solved the problem. If the Nagas have to be won over, we must have a proper moral and political approach also. That must be constantly there. Whatever we may or we may not do, the political approach must be constantly there and at no point must it be given up. Even if sometimes military action has to be taken or administrative actions have to be taken, it does not mean that the political approach has to be diluted or compromised or given up. It is essentially a political problem and a solution has to be found. It is the same with Kashmir. There are some people in the State of Jammu and Kashmir who according to me nurse grievances but voice wrong demands. If some people talk about separation or talk about self-determination or some such thing, they are obviously raising wrong slogans. India cannot entertain a separatist slogan of that kind which seeks to take a part of Kashmir or a part of Jammu and Kashmir out of India or put the status of the State of Jammu and Kashmir in a sort of uncertain category. It is an established fact by Constitution, by law, in every way, that the State of Jammu and Kashmir is a part of the Indian Union and it will remain a part of India. But unfortunately some people there do not share our views in this matter. They are at the same time Indian citizens living in the Indian Union. How to approach them? Naturally not by threatening them all the time. We have to evolve certain political, friendly approaches. We have to go to the root of the problem as to why some people should think that they can not remain with us or should put forward slogans of self-determination or be responsive to such slogans when they are given by a certain power—whether it is China or Pakistan, I am not concerned with that at the moment. We should ask ourselves why it is so. I think that is a question we should bear in mind and find a satisfactory answer. It has to be admitted that the people of Jammu and Kashmir, specially of the Kashmir Valley, have certain legitimate grievances. These grievances are no doubt exploited by certain people, but the fact that some people inimical to our country are seeking to exploit the grievances does not mean that we should not pay heed to the grievances, try to understand them and try to remove them as far as possible within the framework of the Indian Union.

SHRI ABID ALI (Maharashtra) : For instance?

SHRI BHUPESH GUPTA : Many grievances.

SHRI ABID ALI : Which are legitimate?

SHRI BHUPESH GUPTA : Many grievances, you know.

SHRI ABID ALI : Tell me one or two atleast.

SHRI BHUPESH GUPTA : Do not disturb me.

SHRI ABID ALI : Just for my education, at least one or two legitimate grievances.

SHRI BHUPESH GUPTA : I am giving. Just a minute. Wait a minute. For once you have asked a relevant question and I should answer. for example, the monies that have been spent over the past twenty years have been misused, have not been spent for the purposes for which the Government of India sanctioned it. This is a serious grievance. If you sanction special money for Kashmir with a view to bringing about certain development and which is in the larger interest of the people of Kashmir, so that they could be integrated properly, the people of Kashmir, specially of the valley, feel that the money had been misused for a certain section, even for certain families. After all, you know the former Chief Minister himself was in the dock. You can understand what the feelings would have been in such a situation when they see such things. It is a known fact that the monies have not been properly utilised. If the money had been utilised in a proper way, at least for the purposes for which they were given, faithfully, some of the grievances would have been removed and people would have seen a little of better life. That has not happened. Let us admit it frankly, rectify the errors and plug the loopholes. That is how we should approach.

Secondly, it is also a fact that there is an attempt on the part of certain people from outside the State of Jammu and Kashmir to grab land or to acquire certain properties there which the Kashmir people do not view with sympathy. We can understand it Such things even happen in Bombay, even in other States as you see. When unemployment develops, people feel that outsiders should not come although they are part of the same India and fellow citizens. If that could happen in the city of Bombay and the grievances could accumulate there, you can well imagine in a relatively backward area, industrially, how the people would feel. I have been to Kashmir several times. It is a picture of poverty and sorrow. It is a beautiful place if you take into account the gift of nature. It is misery, agony, sorrow, privation and hardship all over if you take into account the gift of man. That is how we view this. Obviously that has given rise to a lot of grievances. These are being exploited. I think they should be all looked into by the Government and removed. Also the democratic system should be extended, expanded in Kashmir. It is no use trying to hoodwink the people by saying that everything is all right. The people do not think so. Now things have a little improved, I agree. In the past twenty years people felt that the parliamentary institutions as they are known had not been properly run. Elections had been rigged. Corruption had taken place. Intimidation had taken place. Certain families had tried to gain advantage out of the patronage given by the Government of India. This is a very common feeling in Kashmir. Am I to understand that these people who make these criticisms are all wrong or they have become anti-national? Not at all. There may be some elements, but by and large people are national. It is our job to make them feel at home, as one of us, as indeed they are one of us. That is how we should approach this matter.

I am chary of giving powers to this Government because I do not know how the Government is going to use power. I can understand if the Government is democratic, decent and reasonable, and sometimes certain powers have to be given to it even if these powers by themselves are not very acceptable and agreeable things. But here is a Government which behaves in a very irresponsible manner. They are past-masters in abusing power and authority. We have seen how they misused the Defence of India Rules. We have seen how they misuse other laws and powers in their possession. We hope this power would not be used in this manner, would not be misused in the way they had in the past misused power. That I would like to say. First of all let us remember that it is a democracy. We should not be so sensitive. In England anybody can say anything. In England if somebody gets up in Hyde Park, in Trafalgar Square, and says that Wales should be delivered to the Irish Republic, he commits no offence. He may be called a mad man or some such thing but nobody bothers about it. Here we kick up such a row if somebody says someting of that sort, border or some such thing, or even about the implementation of the award on Beru Bari. Whether you agree or do not agree is a different matter but you create such a row in this country. Is our Republic so brittle, so fragile, so weak that if a few people say something somewhere immediately we think as if the whole thing is going to rack and ruin and the Republic will be broken? Not at all. We are quite strong. Let us have a little confidence. In France anybody can say anything with regard to the territory. Nobody bothers about it.

[Shri Bhupesh Gupta]

It is an inferiority complex from which we are suffering sometimes. Suppose in America a citizen gets up and says that they should give Pennsylvania or some other place to somebody else, people may treat him as a mad man, but nobody starts an adjournment motion in the Congress or in the Senate or elsewhere. I think we should realise that we too are solid. You may dislike it but it is not legal problem. Political public opinion should be so strong and fundamental loyalty should be so strong that we do not need such a thing. Even if some people perchance said certain things, they should be treated as lunatics.

Now somebody made a statement. Whether the statement is right or wrong, the Home Ministry had the cheek to write a letter to the Chief Minister of Kerala, "Come here, we shall discuss with you". Who are you? If you think that you should discuss with Mr. Namboodiripad, go to Kerala and consult with him. Who are you to write a letter asking him to come, summoning him that way? Is this the way to maintain the integrity of the country? Mr. Namboodiribad may have his own ideas about the statement.

He may have his own meaning. We can read the statement, we can come to our conclusion. Well, whether it is wise or it is unwise I do not go into this aspect. But if the Central Government thinks that the matter needs to be discussed—he does not think it necessary to discuss it with you—who are you to summon and ask him to come to Delhi? Rightly has Mr. E. M. S. Namboodiripad said, "I am not going to Delhi. If they want, let them come here." That is the way the Central Government should be treated. I congratulate Mr. E. M. S. Namboodiripad for the way in which he has replied. We have discussed it in Parliament. We can discuss it. The statement is there. You may or may not like it. You may put any interpretation on it as you like. But that is not the way to treat him. A party which is in need of any clarification should go to him and seek it rather than summoning him to Delhi and revealing in Parliament that we have asked him to come to Parliament, even when he has not received the letter. When Mr. Chavan made the statement here, the same day or the day after Mr. E. M. S. Namboodripad was asked in Trivandrum whether he has received such a letter and he made it known that he had not received any such letter. Even before he receives the letter we are told that he has been asked to come. May I tell, you Gentlemen of the Treasury Benches, that neither Mr. Ajoy Mukherjee nor Mr. Namboodripad is going to oblige you like this. Rules of the game should be played by all. If anybody had done anything wrong, by all means let it be discussed and debated, but not in this way, in the way you adopt.

Mr. Vice-Chairman, before I finally sit down, I would say that much fuss is made about the Constitution. I am tired of it. We have got nearly 400 articles of the Constitution. Every single article of the Constitution can be changed and the Constitution provides the machinery for the change. Suppose I say that I whould like to alter from article 1 to article 394 of the Constitution, that I would like to change them, am I committing a crime? The Constitution says that I can change it. Parliament has been given the power to change it. The procedure has been laid down. Of course, the problem has now arisen of the Supreme Court's decision. But everything is there. What is wrong if I say that I want to change one or all the articles of the Constitution? The Congress itself has changed it 22 times, sometimes for good reasons and sometimes for bad reasons. Nobody thought that they were doing anything particularly wrong or, well, unconstitutional on that account. It is for the Supreme Court to say after I amend the Constitution. Who are you to sit in judgment over that thing. It is not a question of language. And certainly, the Indian Constitution is a living Constitution and it is bound to undergo changes. Any living constitution, any written constitution, does undergo change with the passage of time. Within twenty years, we have changed this Constitution 22 times, on an average once a year. Well, who has told you that the pace may not be increased? Even then, I may find it necessary to increase the pace of change. Therefore, why all this fuss about this change. Surely, big social changes will take place. The demands and expressions of the people will be met. Political change in the political life of the country will take place. The complexion of Parliament will also change. Institutions will also change. And surely, the judges themselves will find it necessary to change the Constitution, as those who are occupying the Treasury Benches and those sitting in Parliament might consider it necessary, with moving times, to change it, to meet the demands of a dynamic situation and social life. All that is there. It is sheer bunkum, it is sheer propaganda on the part of the Mr.Nijalingappa, Mr. S. K. Patil and others. For example, Mr. S. K. Patil, he has dedic ted his life . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : It is time to wind up.

SHRI BHUPESH GUPTA : Do not finish Mr. S. K. Patil. He says, I am not a butcher of the Constitution. Mr. Vice-Chairman, Mr. S. K. Patel, well, may say so —"I am not going to be the butcher of democracy". Why does he say so? It is because he feels that bank nationalisation amounts to a butchery of democracy.

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) (Tamil Nadu) : How does bank nationalisation come here?

SHRI BHUPESH GUPTA : I tell you. The Constitution. .

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) : If he wants to speak about it he has got an opportunity next week as long as he likes.

SHRI BHUPESH GUPTA : I entirely agree because our esteemed friend, Shrimati Lalitha Rajagopalan is always very irrelevant and she has asked me not to speak on it. I will not, since she advises me, and I accept it in all humility. Why should I speak on bank nationalisation? I am speaking of Mr. S. K. Patil and the butchery of the Constitution. And then he said, "I will not hesitate even if I have to lay down my life". He said that the butchery of the constitution is taking place and all this kind of things—

> "Addressing a small crowd at Goregaon in north Bombay on Sunday, he said : "I am not opposed to socialism but I would not tolerate that type of socialism which uproots democracy".

He knows that bank nationalisation is a social programme

> "I cannot sit idle while the democracy is being butchered."

Hence, Mr. S. K. Patil, of all people, saying all such things. Therefore, I do not...

SHRI A. D. MANI (Madhya Pradesh) : On a point of order. It is not proper for Mr. Bhupesh Gupta to refer to a Member of the other House This is a parliamentary debate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Yes. It is time.

SHRI A. D. MANI : Sir, why should Mr. Bhupesh Gupta refer to a Member of the other House and say such type of things in the way he does? I think we should maintain some decorum and order in this House. Whatever you may think of Mr. S. K. Patil, he is also a Member of Parliament, as you are a Member of this House. You cannot refer to him.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is not a point of order. Mr. S. K. Patil and all those people are attacking us every day. Mr. Rajnarain has mentioned about it. I have mentioned about it. And if you go through the proceedings, Mr. Mani, you will find ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : What you are quoting does not come under this Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Mani does not know anything nowadays except the Hitavada. He reads two things—his own speech he delivers here and the Hitavada. Two things he reads.

SHRI A. D. MANI : The New Age.

SHRI BHUPESH GUPTA : You are saying such a thing.

So, this is the kind of statement made. I have made this point because it is necessary to bring out the fundamental things. This is a law which affects the fundamental rights of the citizens. Please understand it. Therefore, we should be particularly careful. The mentality of the Government leaves me in no doubt that they are liable to misuse such powers. That is my fear. And the way they are behaving—some of the men in high positions in ruling party—makes me feel that they are going to misuse these powers, and therefore I mentioned it. I do not wish to go into it any more.

Finally, Mr. Vice-Chairman, I appeal to you. Save our Parliamentary democracy, whatever is left of it, from the hands of Mr. S. K. Patil and the great Syndicate, which is out to commit the greatest butchery of the Constitution and democracy in the country.

SHRI KESAVAN THAZHAVA (Kerala) : Sir, the Government wants to extend the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act to the State of Jammu and Kashmir through this amending Bill.

[THE DEPUTY CHAIRMAN IN THE CHAIR.]

[Shri Kesavan Thazhava]

My submission is that there is a provision in the Constitution giving some special status to the State of Jammu and Kashmir. It is because of that fact that the provisions of the original Act were not introduced in that State. My submission is that by this Bill the Government is really umdermining the provisions of the Constitution. I say that they are wrecking the Constitution because a special status was conferred on the State of Jammu and Kashmir by the Constitution, including special privileges. My submission is that it is not possible to bring Jammu and Kashmir to our side. I also ask the hon. Minister in charge of this Bill: Is it intended to extend this to Azad Kashmir which is now in possession of Pakistan?

Pakistan took Azad Kashmir by force and still continues to be in possession of the same. But legally Azad Kashmir is part of Jammu and Kashmir. What I want to know is whether the provisions of this Bill are intended to be applicable to Azad Kashmir also. For the last twenty years Azad Kashmir is in the possession of Pakistan and the Government of India could not, either by negotiation otherwise take it back. They say the the question is still under negotiation. My submission is that it is not possible to take back Azad Kashmir by any amount of negotiations. Either we must take it back by force or leave it for good. That is the only course tha t can be adopted.

There is another thing on which I have to make my submission in this connection. It is reported that huge amounts are spent in Jammu and Kashmir to get the sympathies of the Kashmiris. I want to know whether Government will really get sympathy of the Kashmiris in this way. Whether they get the sympathy of the Kashmiris or not, I want the Government not to spend any more money on Kashmir because it would be fruitless in the end because the Congress, ever since it came into power after independence, was doing things in such a way as to alienate the sympathy of the Kashmiris from us. So my submission is that the Government has failed in its duty to safeguard the interest of India from getting the Jammu and Kashmir State people to our side. According to my information and also from the information received from persons who are coming from that side though they are getting our money, all kinds of privileges and advantages, their sympathy is not with us. So my humble submission is that the Government must be very careful in spending more money in Kashmir.

Madam, if they want Kashmir to remain as a part of India, then they should allow the people of India from the various other States to go over there and settle down in vast areas that are laying fallow. Give them all protection. We can persuade lakhs of people from other States to go over to Kashmir and to settle down there. Give them land and protection and money to build houses. That is the only way you can keep Kashmir with you. So my submission is that by introducing legislation bit by bit in Jammu and Kashmir it will never be possible to win the sympathy of the Kashmiris and bring them to our side. Do something tangible. Take Azad Kashmir by force. There is nothing wrong in it. It is our country. Pakistan took it by force and we will be only trying to get it back. Use force and take it back, I have no objection. Also allow as many people to go and settle down in Kashmir. That is the only solution to keep Kashmir with us. And not spend a single pie over Jammu and Kashmir. Spend it on other parts.

SHRI ABID ALI : Madam, I wish all the enactments passed by Parliament all made equally applicable to the Jammu and Kashmir area as well as they are applicable to the rest of the country. Kashmir is as much a part of India as are Bombay, Madhya Pradesh, Tamil Nadu and others. Of course, being a backward area it should be treated with more generosity. But in all other matters it should be treated on par with other States. If necessary, the Government may bring in a small measure saying that all enactments which are as yet not applicable to Jammu and Kashmir should be applicable to that State, of course depending upon the wish of the Government there to utilise these enactments.

Madam, it is true that this Government has large powers and honourable Member said, but my complaint is that these powers are not being utilised. Mr. Bhupesh Gupta was talking about some imaginery things butchery of the Constitution and all that The statement that he mentioned I have

read. But, as I have already said, my complaint against this Government is that they do not take action against those who day in and day out want to commit butchery on the Constitution and destroy all that the nation stands for. When I asked him to mention what his grievance was he mentioned two things : (1) expolitation by those people who go and settle down there. But now Mr. Kesava , who just spoke, advised large numbers of people from other States to be allowed to settle down there; (2) Misuse of money. That way Communist ministers have misused plenty of money in Kerala and other places for which there has been so much of agitation. If some Communist Ministers or other Ministers misuse public money, that does not mean the people should become angry with the Central Government. They should certainly become angry with the Minister concerned or the party to which he belongs except to the extent that the Central Goverernment does not take strong action against the communists.

He mentioned something about Bombay. I know why he is so much against that organisation. It is because that organization is genuinely not prepared to tolerate communist actions, and it is also a fact that because of that organisation's efforts—although I do not agree with most of what they do—Communists in Bombay have been almost liquidated. Therefore, naturally, he will be angry. I understand that. But he asks why Namboodiripad should be called to Delhi. Nobody told him to come here. He was requested. If he does not come, well, it is their business. He mentioned France, England and the U.S.A. If such a behaviour would have been there by anybody in any position he would have been arrested and put behind the bars. It is this Congress Government only which behaves in this lenient fashion and I do not know how long they will behave that way. They are tolerating so much of nonsense. Such antinational Minister should be immediately dismissed which any other sensible Government would have done, handcuffed him and put him behind the bars.

SHRI BHUPESH GUPTA : It is only because of your handcuffs that now there are only 9 Congress M.L.As, not even enough for a foot-ball team.

SHRI ABID ALI : It is because of this attitude of the Government that the country is in this position. It is not to-day I am saying this; I have been saying this always, I have been giving warning after warning. Once when Jawaharlalji was sitting here, one Communist Member said "I support this measure of the Government," Immediately Jawaharlalji stood up and said "What wrong have I done? Let me re-think my position. Something wrong is there. Why then are the Communists supporting this measure?" That was real Jawaharlalji Gradually and gradually, thing went on to reach the state in which we are to-day.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार): श्रीमती इन्दिरा गांधी को पता नहीं लगता कि कम्युनिस्ट क्यों समर्थन कर रहे हैं ।

SHRI ABID ALI : Therefore, if our Government had behaved on the lines it ought to have behaved, on the lines of a democratic institution, then the interests of this country would not have been in jeopardy as it is today.

SHRI BHUPESH GUPTA : By 1972 you will be finished.

SHRI ABID ALI : Let us see what happens in 1972. Who will be finished? Only Russia or China; who else can be finished? Those who do not stand by the interests and the needs of the country are to be finished. Nothing else can happened—let him be sure about it. Then about the way he asked "Who is Mr. Chavan to call him?" unfortunately, Mr. Chavan does not assert himself. Therefore the hon. Member has got this sort of encouragement to get up and put such a question. He was talking about Hyde Park. You have also seen Hyde Park and I have also seen it.

SHRI A. D. MANI : He spoke there.

SHRI ABID ALI : Only to half a dozen people. He was perhaps hiding there. What he says is true that a mad man only can stand up and say "Kill Mr. Bhupesh Gupta". And nobody takes serious notice of these people because most of the people talking there are madcaps. So, that standard is different. But can anyone, I ask, speak things of the kind that the Communits are talking in this House or outside? He says that Mr. Patil has committed butchery of the Constitution. It is these people who seek to destroy the Constitution and who go

[Shri Abid Ali]

to the extent of saying that these courts are capitalist courts, when the courts have been giving them so much liberty, when the courts have been coming to their help from time to time...

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैं चाहता हूं कि एक दिन पूरा रखा जाय, आधा दिन भूपेश बोले, आधा दिन आप बोलें, कोई विषय की लिमिट न रहे ।

श्री आबिद अली : अन्धों के आगे रोना, अपनी आंखें खोना । बोला क्या जाय ? इन लोगों को बोलें । इन लोगों को तो फांसी चढ़ाना चाहिए । ये हमसे क्या बोलेंगे ? ये हैं किस का बिल ? ये लोग जबान नहीं समझते हैं डेमोक्रेसी आनेस्टी, ईमानदारी और इन्टेग्रेटी की । मणि साहब कह रहे थे कि इस हाउस की डिगनिटी रखनी चाहिए । डिगनिटी और ये लोग, डेमोक्रेसी और ये लोग, शराफत और ये लोग ? कहां है आप हुजूर, छोड़िए इन लोगों को, हमारे साथ आइए, इन गद्दारों से तो बचिए ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप की प्रधान मन्त्री तो इनको साथ ले जा रही हैं ।

श्री आबिद अली : आप तो बुरा न कीजिए आपने बिहार और यू० पी० में उनके साथ मिनिस्ट्री क्यों बनाई ?

SHRIMATI LALITHA (RAJAGOPALAN) : Madam Deputy Chairman, at the outset I wholeheartedly support this Unlawful Activities (Prevention) Amendment Bill, 1969. Strikes, unrest, destruction of public properties are happening every day and have assumed gigantic proportions. I would not attribute this only to the general frustration that is existing in the counrty, but to the anti-national elements who think that only with a revolution we can get salvation. I am shappy that this Bill has been extended to the State of Jammu and Kashmir. We have been reiterating every time that Jammu and Kashmir is an integral part of our country. Every time this question was raised in Pakistan or in our own country, we had said again and again that Jammu and Kashmir is an integral part of this courty. But it is surprising that the Home Minister did not bring forward this Bill earlier.

Now, the unlawful activities are on the increase and every day we find in the newspapers that the activities of the Naxalities and others are on the increase, even in Jammu and Kashmir also. Jammu and Kashmir is a vital part in our border security and it is all the more reason why this Act should have been extended to that region long before.

In this connection, I would like to draw the attention of the Home Minister to the visit of Mr. Jyoti Basu, Deputy Chief Minister of West Bengal, to South India—perhaps to Tanjore; I cannot recollect it now. Normally law and order in connection with his visit should be entrusted to the State Police and the Home Minister of that State should be concerned with it. But I find from the newspapers that instead of the State Police, it was the Red Guards who helped him to conduct his programmes and the Police were nowhere in the picture and they were there only as spectators. I would like the Home Minister to enlighten us as to whether this newspaper report is true and whether he has got any information in his regard from Home Minister of Tamil Nadu.

Lastly, when people in responsible positions like Shri E. M. S. Nambudiripad and Shri A. K. Gopalan thereaten and try to break the Constitution, we should see that this measure deals with such attemps strongly. I hope when such offences are committed, whether by people in responsible positions or others the punishment would be very severe there would be no sympathy for them and they would be dealt with an iron hand.

I wholeheartedly support this Bill.

श्री ना० कृ० शेजवालकर (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपाध्यक्षा महोदया, वर्तमान बिल को काश्मीर में लागू करने के लिए एमेंड किया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह कार्यवाही करने के लिए शासन की तरफ से यह विलम्ब क्यों हुआ । वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि भारत के संविधान में ही इस दृष्टी से संशोधन कर देना नितान्त आवश्यक है जिससे काश्मीर के लिए पृथक से कोई भी कानून बनाना न पड़े हम यह देखते हैं कि कोई भी जब कानन बनता है तो उसमें जम्मू और काश्मीर को छोड दिया

जाता है बल्कि दौड़ना पड़ता है और बाद में इस प्रकार के संशोधनों के द्वारा वे कानून वहां पर लागू किए जाते हैं। क्या जिन कारणों के आधार पर या जिन परिस्थितियों के आधार पर 1967 का कानून सारे भारतवर्ष के लिए लागू किया गया क्या वे परिस्थितियां उस समय काश्मीर के अन्दर नहीं थीं और क्या आज वे पैदा हो गई हैं? आश्चर्य की बात तो यह

4 P.M. है कि आज यह जो कानून बनाया गया है, जो अमेंडमेंट रखा जा रहा है इस के अंदर भी यह सुझाया गया है कि

> "Provided that it shall come into force in the State of Jammu and Kashmir on such a date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

यानी अभी भी कोई विशिष्ट तिथि नियुक्त करने की आवश्यकता है। आज भी इस में यह नहीं लिखा गया कि इमीडियेटली यह लागू हो जायगा। उस के लिए भी शासन के द्वारा एक पृथक् तिथि नियुक्त की जायगी। अगर ऐसा ही होना है तो आज इस की क्या आवश्यकता है और जैसी अभी चर्चा हुई है कि कॉन्स्टीट्यूशन तोड़ देने की बात करने तक की जुर्रत जब लोगों में हो गयी है और यह शासन इस कानून के अन्तर्गत भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता है तो मैं समझ नहीं सकता कि जम्मू काश्मीर में इस ढीले तरीके से इस कानून को आगे बढ़ाने से क्या लाभ होने वाला है। वास्तविकता तो यह है कि अब समय आ गया है, जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया, कि काश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग अब वास्तविक रूप से माना जाय। वहां पर हम लोग आजादी से जा सकें, वहां बस सकें, भारत के दूसरे नागरिक वहां जा कर सम्पत्ति खरीद सकें और वहां की जमीन का उपयोग कर सकें और इसी प्रकार वहां के नागरिक इधर आ सकें और उन से अलग प्रकार का व्यवहार न हो। यह अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार प्रत्येक कानून के अंदर संशोधन ला कर इस तरह का काम चलेगा नहीं। वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि भारत का जो संविधान है उस में संशोधन इस उद्देश्य को सामने रखते हुए किया जाय कि काश्मीर भारत के अन्य प्रदेशों जैसा ही एक प्रदेश है। आज इस की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है।

अभी जो एक नयी बात यहां पर कही गयी कि काश्मीर की जनता की कुछ ग्रीविएंसेज हैं, माननीय सदस्य श्री आबिद अली ने जब प्रश्न पूछा तो उस का कोई उत्तर माननीय सदस्य नहीं दे सके और केवल व्यय के बारे कह कर टाल गये क्योंकि इस बारे में उन से बारबार, पूछा जाने पर भी उन्होंने उस बात को टाल दिया। वास्तविकता यह है कि आपत्ति अगर किसी को हो सकती तो भारत के दूसरे प्रदेशों को हो सकती है जहां से करोड़ों रुपया काश्मीर के लिए जाता है और वहां पर उस को व्यय किया जाता है। परन्तु उन को आपत्ति इस लिए नहीं है कि सारे भारत के लोग काश्मीर को अपने देश का एक अविभाज्य अंग मानते हैं और इस लिए उन बंधुओं के लिए जो व्यय करने की आवश्यकता है वह व्यय किया जाय इस बारे में किसी को आपत्ति नहीं होती किन्तु, वास्तविकता दूसरी है। कहने को जो प्लीली जाती है, जो आड ली जाती है उस सारी बात के पीछे एक साजिश भी छिपी हुई है और इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग एक प्रकार की साजिश ले कर चलते हैं कि भारत किसी प्रकार से एक राष्ट्र न बन सके इस सदन में ही पिछले समय कुछ महानुभावों ने यह कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत तो अनेक राष्ट्रों का समूह है। इस प्रकार का थ्योरीज भी इस सदन में हम लोगों के सामने रखी गयी। इस तरह की एक साजिश अपने देश में आज चल रही है कि भारत को एक राष्ट्र नहीं बनने देना चाहिए, इस बात का पता लगता है। और वह चाहे किसी तरह से हो। जनतंत्र में इन लोगों को कोई विश्वास नहीं है इस से इस बात का भी पता लगता है। उन को तो किसी तरह से सत्ता हथियाने के लिए जनतंत्र का सहारा लेना है और वे चाहते हैं कि किसी तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ कर

[श्री० ना० कृ० शेजवालकर]

रख दिया जाय और उन के गुरु देश जो हैं उन मे जिस प्रकार की सत्ता चल रही है जहा फासिज्म है, अधिनायकवाद है, जहा नागरिक। के लिए कोई आजादी नही है इस प्रकार की स्थिति भारत मे लाने के लिए उन का एक षडयत्र है और उस के लिए ही वे इन सारी बातो का समर्थन करते है। किन्तु दुख इस बात का है कि यहाँ का बहुमत दल जो है उस के कुछ लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, उन के अदर भी इस तरह के तत्व हैं कि जो इस बात को स्वीकार करते है और इसी लिए हमारा देश आज एक सकट के काल से गुजर रहा है। हम इस स्थिति को देख रहे हैं। आज पब्लिक ट्रायस जैसी चीजे बगाल मे शुरू हो गयी हैं, भीड के हमले होते है और वहा लोगो की जान खतरे मे है। वहा आनन्द बाजार पत्रिका अगर कोई समाचार प्रकाशित करती है तो उस के कारण उस का दफ्तर जला दिया जाता है, उस के सामान को आग लगा दी जाती है। इस प्रकार की स्थिति जहा पर विद्यमान हो वहा लोग जनतत्र की दुहाई दे और उन्ही को पब्लिक प्रीवासेज सामने रखने का अधिकार हो यह दलील मैं समझ नही पाता। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह एक लम्बी साजिश है और इस के द्वारा देश को खड विखड करने का प्रयत्न हो रहा है और यहा के जनसमूह मे विद्रोह पैदा करने की स के दवारा कार्यवाही की जा रही है। मे तो गह मत्री महोदय से निवेदन करूगा कि वास्तव में आज के कानून के अदर भी ऐसे कार्यों को रोकना सभव है और अगर उन को रोकने का प्रयोग करना है तो वे करें। अभी देर नही हुई है। जिस प्रकार की अपमानजनक स्थिति अभी हुई कि एक मुख्य मत्री द्वारा केन्द्र के शासन की अवहेलना की गयी यह कोई अच्छी बात नही है। इस के लिए शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए और जो वर्तमान कानून है उन के अतर्गत भी उन के लिए कार्यवाही की जा सकती है।

जहा तक इस बिल का सवाल है इस मे कोई दो राये नही हो सकती, जब मैं कह रहा हू कि पूरे देश मे एक तरह का कानून होना चाहिए तो इस को एक्सटेड करने मे किसी को कोई आपत्ति नही हो सकती, लेकिन हर मामूली फोडे फुसी के लिए दवा करना उचित नही है। एक ऐसी दवा खोजनी चाहिए ताकि बीमारी जड से अच्छी हो जाय। इसी लिए इस प्रकार का सशोधन सविधान के अदर लाना अत्यन्त आवश्यक है और जैसा कि मैं पहले कह चुका हू कि अभी तो इस बिल मे यह पता नही लग रहा है कि यह कानून लगेगा कब से। जब से नोटिफिकेशन होगा तब से यह कानून लागू होगा। इस की क्या आवश्यकता है यह समझ म नही आ रहा है। अगर वहा पर इसे लागू करने की आवश्यकता है तो इस प्राविजो को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए और इस की कोई आवश्यकता भी नही है। धन्यवाद।

श्री जगत नारायण (हरियाणा) : वाइस चेयरमैन साहब, मैं इस बिल के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हू। मगर अगर इस बिल को लाइब्रेरी मे जीनत ही हासिल करना है तो इस का कोई फायदा नही है। मैं चाहूगा कि वजीर साहब अनलाफुल एक्टिविटिज को डिफाइन करे कि अनलाफुल एक्टिविटिज मे यह बात आती है कि नही कि जिस आईन को हम लेज लेते हैं एलेक्शन लडते वक्त और फिर जब यहा के मेम्बर बनते है या विधान सभा के मेम्बर बनते है तो उस वक्त कोंस्टीट्युशन को हलफ लेते है और उस के बाद भी जो लोग इतना करते हुए भी यह कहे कि हम कास्टीट्युशन को रद्द करना चाहते है तो ऐसी सूरत मे यह जो एक्ट अनलाफुल एक्टिविटिज के बारे में यह उन पर लागू होता है या नही। पिछले दो साल से यह एक्ट पास हुआ हुआ है लेकिन देखे कि भारतवष मे हालात क्या है। दो साल के अरसे मे जितनी हमारे कास्टीट्यूशन की मिट्टो पलीद हो गयी है, उस के खिलाफ कहा गया है, उस के खिलाफ किया गया है मे समझता हू कि उतना दो साल के

पहले कभी नहीं किया गया था। अभी अभी हमारे एक बुजुर्ग साहब ने कहा कि हमारा हक है कि हम कास्टीट्यूशन को दफा 1 से ले कर दफा 394 तक अमेंड कर सकते हैं, अमेंड करना दूसरी बात है और उस को रद्द करना दूसरी बात है और खास कर उस आदमी के लिए ऐसा कहना कि जो इस हाउस का मेम्बर भी नहीं है, वह तो अमेंड करने की बात भी नहीं कह सकता। अगर वह कहे कि हम इस कानून को रद्द करना चाहते हैं तो कैसे आप समझते है कि उन को एक्टिविटीज अनलाफुल नहीं है। इसी तरह से, मैं वजीर साहब से पूछना चाहता हू कि, माओ की तस्वीरें लगा कर जलसे किये जाते हैं और माओ के थाट्स यहा पर लाखों की तादाद मे बेचे जाते है और फिर उस के साथ साथ यह भी होता है कि नारे लगाये जाते है 'माओ–जिन्दाबाद', तो मैं जानना चाहता हूं कि अनलाफुल एक्टिविटीज में यह चीजे आती है या नही? और जिस ढग से यह ब्लडी रेवोल्यूशन की टाक की जाती है . . .

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : शतरंज सिनेमा जिसमें के माओ के खिलाफ कुछ बोलते है उसको बन्द करवाते है।

श्री जगत नारायण : मेरे भाई ने सिनेमा वाली बात कही है तो अपने देश में माओ के खिलाफ सिनेमा में तस्वीर नही दिखा सकते, अपने देश की बनी हुई तस्वीर नहीं दिखा सकते, यह हालत है। तो यह सब अनलाफुल एक्टीविटीज में आता है या नही आता। आराम से जो मेम्बर आते है उनका बहुत ठीक कहना है कि दो साल से यह एक्ट बना है तो अगर उसको लाइब्रेरी की जीनत बना कर ही रखना है तो फिर क्या फायदा है इस बिल को पास करने से।

दूसरी बात यह है कि पिछले दो साल से यह एक्ट है और अब यह ख्याल आया है कि सको जम्मू काश्मीर में भी लागू करना चाहिये मुझे पिछली मर्तबा श्रीनगर में जाने का मौका मिला। मेंने देखा कि हर दीवार पर कांग्रेस मुर्दाबाद, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद, इन्दिरा मुर्दाबाद, हिन्दुस्तानी काश्मीर छोड दो के नारे लिखे हुये थे। यहा मेहता जो बैठे हुए हैं वह बतायेगे जो बडे बडे मकान थे, मस्जिदे थीं, वहां यह पढ कर मैं आया हू, उसको फोटो ले कर मैं आया था और हमने अपने अखबार में फोटो भी छापा था। तो दो साल तक आपको इसका ख्याल नहीं आया कि जम्मू काश्मीर में भी इसको लागू करना है। यह ठीक है कि वहा कुछ हालत पहले से बदली है लेकिन उसके बावजुद वहां यह हालत है। तो मैं आपको कहना चाहता हू कि जब कभी आप बिल बनावे तो उसमें साथ मे ही जम्मू और काश्मीर पहले ही शामिल कर दिया जाय, यों तो मैं समझता हू कि शामिल करने की जरूरत ही नहीं है जब कि, जम्मू और काश्मीर हिन्दुस्तान का अग है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : जब तक आर्टिकिल 370 है तब तक हम कैसे कर सकते है।

श्री जगत नारायण : लेकिन फिर भी बार बार इसके लिये बिल लाने की क्या जरूरत है।

तो मैं कह रहा था कि अगर आपको इस बिल को वाकई लागू करना है तो आप देखिये कि हर सूबे मे नक्सलाइट पूरे जोर से अपना काम कर रहे है, पूरे जोर से आन्दोलन चला रहे है पजाब से ले कर कलकत्ता तक और कलकत्ता से मद्रास तक सारी जगह नकसलाइट्स का आन्दोलन चल रहा है मगर हमारी सरकार है कि उनके खिलाफ इस अनलाफुल एक्टीविटीज के कानून को लागू नहीं करती। छोड दिया गया है यों ही सारी स्टेट्स को कि जो मर्जी मे आवे वह करें या नहीं करें, यह उन पर मुनहसिर है।

[श्री जगत नारायण]

मैं मद्रास गया तो मैंने देखा कि मद्रास मे दो ऐसे बाजार है जहा कि खुल्लमखुल्ला चीन का माल फरोख्त करते है। वहा बहुत बडा बाजार लगा हुआ है। कोई भी आदमी वहा जाय और जा कर देख सकता है। 20 दिन हुये मद्रास गया था मैंने देखा कि वहा आदमी चीन को स्मगिलशुदा कोई चीज खरीद सकता है, एक सुई से ले कर बडी से बडी चीज खरीद सकता है। तो अदाज लगाईये कि क्या यह अनलाफुल एक्टीविटी नही है।

तो मै कहता हू कि बिल बनाने से क्या फायदा है अगर इस तरह की एक्टीविटीज को रोकथाम नही करनी है। वहा बहुत से ऐसे आदमी है जो कि खुलेआम इन चीजों को बेच रहे है। (*Time bell rings*) तो जैसा कि मैंने कहा पिछले दो सालो से नक्सलाइट्स का आन्दोलन जोर से चल रहा है और उसको रोकने के लिये अगर दो साल के अर्से मे इस कानून को अमल मे नही लाये तो जम्म काश्मीर पर इसको लागू कर के क्या इस कानून को काममे लायेगे, यह हमे शक है। इसलिये मे बडे अदब से वजीर साहब से कहूगा कि मै इस बिल का समर्थक हू और मै समझता हू कि इस बिल को पास करना चाहिये लेकिन पास करने के बाद इस पर अमल भी करना चाहिये ताकि जो लोग हिन्दुस्तान के खिलाफ बगावत का नारा उठा रहे है, हिन्दुस्तान के आईने की धज्जिया उडा रहे है, हिन्दुस्तान के आईन को रेक करना चाहते है उनके ऊपर लागू कर के यह साबित करे वाकई जो बिल पास करते है वह इस नीयत से पास करते है कि बिल को लागू करना है, उस पर अमल करना है। इन अल्फाज के साथ मै बडे अदब से फिर वजीर साहब से कहूगा कि इस कानून पर अमल करने की कोशिश करे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : माननीया, इस विधेयक के दो पहलू है और जिन सम्मानित सदस्यो का भाषण हमने सुना उन्होने दोनो पहलुओ को अलग अलग नही देखा है। उनमे से कईयो ने शुरू किया कहा से और अन्त किया कहाँ।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : आपके पास बैठ बैठ कर यही हालत हो गई है।

श्री राजनारायण : माननीया, अनलाफुल एक्टीविटीज क्या है इसकी परिभाषा इसमे दी हुई है। यह The unlawful activities (Prevention) Act, 1967 है, इसमे अनलाफुल एक्टीविटीज क्या है यह दिया हुआ है :

> (f) "unlawful activity", in relation to an individual or association, means any action taken by such individual or association (whether by committing an act or by words either spoken or written, or by signs or by visible representation or otherwise
>
> (i) which is intended, or supports any claim, to bring about, on any ground whatsoever, the secession of a part of the territory of India or the secession of a part of the territory of India from the Union, which incites any individual or group of individuals to bring about such cession or secession,"

यह विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) का जो कानून है उसी मे सशोधन करने का यह विधेयक है। यह कानून अच्छा है या यह कानून खराब है इस पर इस समय विवाद नही है, विवाद यह है कि यह कानून काश्मीर-जम्मू मे लगाया जाय या काश्मीर-जम्मू मे न लगाया जाय। इस समय यह विधेयक इसी के लिये है कि यह कानून काश्मीर-जम्मू में भी लागू हो या लागू नही हो। मुझे अफसोस है कि ये सरकार जाने या अनजाने मे बुद्धि-विभ्रम मे, व्यूह मे, फसती चली जाती है। जिस समय यह विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप निवारक कानून बना उसी समय उसको बनाने के समय इस बात को साफ करना चाहिये था। बार बार यह सरकार अपनी गल्तियो से देश मे और विदेश मे एक असर पैदा करती रहती है कि जम्मू और काश्मीर भारत का एक विचित्र अग है, वह भारत के अन्य अगो के समान नही है। मै चाहता हू कि अब काफी समय बीत गया है जबकि

इस सरकार को ालिग हो जाना चाहिये। सर्वदा नाबालिग दिमाग से काम करना देश के लिये बहुत ही म जिर हो रहा है, नुकसानदेह हो रहा है। आज यह देश के लिये बहुत ही हानिकारक हो रहा है। इसलिये मैं बहुत ही अदब के साथ आप के द्वारा घर मंत्री से कहूगा कि जो इसका उद्देश्य लिखा हुआ है उस उद्देश्य को आज ही मंत्री महोदय क्यों समझ रहे हैं।

माननीया, इसके उद्देश्यों और कारणों का कथन जो है उसको पढ़ा जाय तो उसमें लिखा गया है :

"चूंकि संसद की अवशिष्ट शक्तियों से सम्बद्ध संविधान का अनुच्छेद 248 और संघ सूची की प्रविष्टि 97 जम्मू-काश्मीर राज्य को उस समय लागू नहीं थी जब वह अधिनियम अधिनियमित किया गया था, इस कारण इस सम्बन्ध में कुछ शंका व्यक्त की गई है ..."

और उसी शंका के निवारण हेतु यह विधेयक आया है। यह शंका उत्पन्न हो सकती है जब तक की अनुच्छेद 370 है, इस सरकार के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई। यह सरकार सोती रहती है और सुषुप्तावस्था में रहती है, फिर कहीं किसी ने कुछ आंख खोल दी तो यह थोड़ा सा उठ जाती है और फिर उठ कर जम्हाने लगती है और जम्हाते जम्हाते सो जाती है। यह स्थिति है।

माननीया, हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। भूपेश जी, आप सुन रहे हैं कि नहीं। मैंने कहा कि हमारे मित्र भूपेश गुप्त जी ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया, इनके भाषण से हमारी तबियत बहुत खुश है।

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : केवल आज ही।

श्री राजनारायण : जी हां। जरा सुनिये। हमारे एक मित्र जो वामपन्थी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हैं, हमने जो उनको समझा तो शुरू तो उन्होंने किया विरोध से और अन्त किया इसके समर्थन से। कह दिया, कि काश्मीर में भारत के विभिन्न प्रदेशों के लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में भर दिया जाय। काश्मीर के लोग इसके बड़े विरोधी हैं। अगर यह व्यवस्था हो जाय तो आयें काश्मीर को समस्या का समाधान हो जाय। जैसा कि हमारे मार्क्सवादी मित्र ने कहा अगर यह हो जाय कि भारत के अन्य भागों से बड़ी से बड़ी तादाद में लोग काश्मीर में जावे तो काश्मीर में अभी जगह काफी है और जाकर के वहां बसें, तो मैं भी समझता हूं कि वर्तमान काश्मोर की जो समस्या है उसका बड़ा समाधान हो जायेगा।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : गुप्त जी ने जो मैरिज पर भाषण दिया उससे भी हल हो जायेगी।

श्री राजनारायण : तो मैं चाहता हूं कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की यह जो साधु सम्मति है इसको सरकार स्वीकार करे। उनकी बात में मैं भी अपनी बात मिलाता हूं। मगर मैं नहीं समझता अंत तक वह इस बात पर खड़े रहेंगे या नहीं। हो सकता है उन्होंने अपने जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको बिना राय लिये जो सही बात है एक देश के नागरिक के लिये, वह बात कह दी।

डा० भाई महावीर : गलती से कह गये।

श्री राजनारायण : एक बात भूपेश जी को मैं यहां पर जरुर कहूंगा कि उन्होंने ठीक कहा। मैडम, एक ही बात को मुझे कसक है। शेख अब्दुल्ला से कई बार हमारी बातें हुई मगर उसने एक सवाल हमसे पूछा, मैं चाहता हू उसका उत्तर यह सरकार दे। उसने कहा कि राजनारायण, तुम करोड़ों करोड़ रुपये काश्मीर में खर्च कर रहे हो, बीस साल हो गये मगर वहां की जनता को प्रजातंत्रीय प्रणाली तुमने ने सिखायी है क्या। और उसकी मैं ईमानदारी मानूंगा उसने एक बात कही। हमने कहा एक बात का जवाब तुम दो, शेख। यदि अब काश्मीर में वोट हो तो क्या वह वोट डेमोक्रेटिक होगा। उसने

[श्री राजनारायण]

कहा, नहीं। मगर भूपेश गुप्त उसको नहीं मानेंगे। शेख अब्दुल्ला ने कहा, नहीं। वह वोट यदि आज काश्मीर में होगा तो वह कम्यूनल टेन्डेन्सी से होगा, उनके मस्तिष्क पर साम्प्रदायिक वातावरण इतना छाया हुआ है कि आज काश्मीर में वोट हो तो मुसलमानों का वोट पाकिस्तान के पक्ष में जायेगा। मगर हम इस वोट को जनतंत्री वोट नहीं मानेंगे, शेख ने ईमानदारी के साथ इस बात को हमसे कबूल किया कि मैं . . .

उपसभापति : क्या फायदा है। अच्छा, और 4 मिनट ले लीजिए।

श्री राजनारायण : मैं इसीलिये कह रहा हूं कि जो नयें पाइन्ट्स उन्होंने उठाए हैं अगर यहां वादविवाद में उन को न कहा जाये तो फिर विवाद का मतलब नहीं, फिर तो सरकार चाहे आर्डिनेन्स निकलवा दिया करे।

डा० भाई महावीर : भूपेश भी ज्यादा बोलते हैं इसलिये उनको भी ज्यादा बोलना पड़ता है।

श्री राजनारायण : मैं भूपेश जी से कहता हूं इस तथ्य को अपनी पार्टी की ओर से लायें अब मैं जयप्रकाश नारायण जी को भी कहना चाहता हूं। जो लोग चाहते हैं काश्मीर में प्लेबिसाइट करा दो, तो क्या आज प्लेबिसाइट प्रीरिक्विजिट है डेमोक्रेटिक वोट के लिये। मैं चाहता हूं कि जितना रुपया वहां खर्च हुआ है, सरकार इसका कारण सोचे, कि हम करोड़ों करोड़ रुपये वहां खर्च कर रहे हैं, हर तरह से पैसा दे रहे हैं।

श्री ओम मेहता (जम्मू और काश्मीर) : भोज पर खर्च होता है।

श्री राजनारायण : यह कहते हैं भोज पर खर्च करते हैं, तो भोज पर मत करो। दूसरी बात भूपेश गुप्त जी ने कही, उसमें भी मैं उनके मत का समर्थक हूं। इसमें नेशनल इन्टीग्रेशन है। मैडम, टेरीटोरियल इन्टीग्रेशन भी है। इन अनलाफुल एक्टिविटी बिल के ऊपर यह दिया गया है। यशवन्त राव चव्हाण को कुछ बात करनी है तो एक नोट दे दिया नम्बूद्रीपाद को। एक सामान्य, सभ्य व्यवहार है जिसको बात करनी है वह जाय। श्री यशवन्तराव चव्हाण की बात करनी है तो कहते हैं नम्बूद्रीपाद यहां आ जाओ। अगर उनको बात करनी है तो वह जाय नम्बूद्रीपाद के यहां, चन्द्रभानु गुप्त के यहां, अजय मुखर्जी के पास। बात करनी है यशवन्तराव को, नम्बूद्रीपाद को नहीं करनी है। हां नम्बुद्रीपाद को बात करनी है तो आएंगे। अगर हमको जरूरत है बात करने की तो हम राम सुभग सिंह के पास जायेंगे। हां, उनको डर होगा, हमारे पास आयेंगे तो अनावश्यक ढंग से लोग रंजीदा हो जाया करते हैं। यह प्रश्न बड़े विवाद का है।

रेलमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह असली बात बताई है।

श्री राजनारायण : इसीलिये इस प्रश्न के मूल को पकड़ो। एकदम से अहंभावी, इगोइस्ट, मत बनो। अहम्भाव लेकर अगर सरकार चलेगी तो आज हमारे देश में अनेक प्रकार के आपकी इस बात को मानता हूं। इस समय उनके दिमाग में साम्प्रदायिक वातावरण इतना समाया हुआ है कि वह शुद्ध जनतंत्र से, स्वतंत्र मस्तिष्क से, वोट नहीं करेंगे। इसलिये इस वोट को हम हर्गिज स्वतंत्र मस्तिष्क का वोट नहीं मानेंगे। मगर भूपेश जी कहते हैं, जब वहां की जनता कहती है तो करा दो। एक तरफ भाई राम सुभग सिंह खड़े हों जायें जिनके पास करोड़ों रुपये, और एक तरफ राजनारायण खड़े हो जायें जिनके पास 5 पैसा भी नहीं।

डा० राम सुभग सिंह : अरे भाई, क्या सही बात बोलते हैं?

श्री राजनारायण : कल्पना।

डा० राम सुभग सिंह : कल्पना क्यों करते हैं। सूरत तो उल्टी है।

श्री राजनारायण : तो क्या यह जनतंत्र है अगर यह वोट होगा तो करोडों रुपया खर्च करके राम सुभग सिंह जी हमारे पक्ष के किसी भी आदमी को हरा देंगे। आज को गरीबी की स्थिति में, जब भुखमरी है मैडम, तो उनको धन बांट कर जीत जायेंगे। मैडम, क्या आप

समझती हैं कि आ। जो कांग्रेस का शासन है वह जनतंत्र है? ह धनतंत्र है। आज कांग्रेस का शासन धनतंत्र है।

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश में आपके शासन में कैसा था।

श्री राजनारायण : उसको दूसरे शब्दों में कह दूं कहीं कहीं ज ति तंत्र है। आज के चुनाव जनतंत्र जैसे हैं ही हीं। इसीलिये राजनीति की समानता, धन को समानता और समाज की समानता, जब क ये तीनों समानताएं नहीं होंगी तब तक जनतं सही रूप में नहीं चलेगा।

(Int rruption)

डा० राम सुभग सिंह : और बोलने की समानता।

श्री राजनारायण : हर विचारक बोलने की समानता कभी नहीं स्वीकार करता क्योंकि जो विचारक है वह अपने विचार देने के लिये बोलेगा, भाषा का प्रयोग करेगा, क्योंकि ज्ञान की उपलब्धि, ज्ञा की रोशनी और ज्ञान की प्रशंसा, विचारों का आदान प्रदान, यही तो भाषा का काम है। भूपेश जी से निवेदन करूंगा कि वह भी इस बात को सोचें...समय की घंटी ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : You should wind up now.

श्री राजनारायण : मैडम मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूं। देखिए मैडम, भूपेश जी 45 मिनट बोले। आप यहां थीं नहीं। और जो पाइन्ट उन्होंने रेज किये ... खतरे हैं ही, आगे भी उत्पन्न होंगे। मेरा निवेदन है कि आज अमरीकी राष्ट्रपति जा आए हैं, हम चाहते हैं कि हम खुल कर सर्वसम्मति से यहां पर आवाज उठाएं जिससे लोगों को मालूम हो कि काश्मीर भारत का है। हम उसको 'अविच्छिन्न' अंग नहीं कहेंगे। हम यह नहीं कहते कि भूपेश जी की नाक उनके शरीर का अविच्छिन्न अंग है। अविच्छिन्न कहना अपने देश को कमजोर करना होगा। बिना सोचे समझे सरकार कहती है, काश्मीर हमारा इन्टीग्रल पार्ट है, अनावश्यक रूप से कहती है। कश्मीर हहमरा है, यह कहे, जैसे हम कहते हैं। इसलिये सरकार की ओर से ऐसे शब्दों का प्रयोग अब आगे से बंद होना चाहिये। यह हमारी नाक हमारा अविच्छिन्न अंग है कहने की बजाय यह नाक हमारी है कहिये। काश्मीर हमारा है। वह हमारी नाक है। अविच्छिन्न शब्द लगाने से केस कमजोर होता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : That will do.

श्री राजनारायण : 2 मिनट हम और मांग रहे हैं। मैं आगे यह कह रहा हूं कि टेरीटोरियल इन्टीग्रिटी के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार सोचे, हमारी राष्ट्रीय एकता एक और तरीके से भ्रमित हो रही है। आज समय नहीं है वरना मैं इसमें संशोधन देता कि जिससे इस बिल की परिधि में वह आ जाये।

हम चाहते हैं कि अनलाफुल एक्टीविटीज़ की परिधि को बढ़ाया जाय और उसमें यह बात रखी जाय कि इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज अगर हरिजन या पिछड़े लोगों के साथ अन्याय करता है, विद्वेष मूलक काम करता है, तो वह भी अनलाफुल एक्टीविटिज़ के अन्दर माना जायेगा। अगर कोई भी एसोसिएशन इस तरह का काम करता है तो उसे भी अनलाफुल एक्टीविटिज़ के अन्दर माना जायेगा।

इस चीज़ को अनलाफुल एक्टीविटिज़ के अन्दर क्यों न माना जाय? इसके कई कारण है, जैसे मिर्जापुर के गोपाल फार्म में एक हरिजन लड़की को गोली मार दी गई जिसकी वजह से डी०आइ०जी का बेटा तथा उप मुख्य मंत्री का बेटा इस झगड़े के कारण बने हैं। तो इस तरह का जो ऐक्ट वहां पर किया गया है, उसको अनलाफुल एक्टीविटिज़ माना जाना चाहिये।

माननीया, इसी तरह से बाराबंकी जिले में एक 4 वर्ष के बच्चे की बलि कर दी जाती है। तो मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के जो काम होते हैं उन्हें अनलाफुल एक्टीविटिज़ के अन्दर आना चाहिये। मैं चाहता हूं कि अनलाफुल एक्टीविटिज़ की परिधि को बढ़ाया

[श्री राजनारायण]

जाय और आज जो हरिजनों के साथ घृणा का व्यवहार हो रहा है, उनको नीचे करने का व्यवहार हो रहा है, उनको समाज से तिरस्कृत करने का व्यवहार हो रहा है, उस व्यवहार को अनलाफुल एक्टीविटिज के अन्दर माना जाना चाहिये। इस परिधि में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिया जाय और उनको अधिक से अधिक सजा की व्यवस्था की जाय। अगर सरकार ऐसा करती है तो मैं अनुगृहीत हूंगा।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam Deputy Chairman, I am glad that most of the hon. Members who took part in this debate have supported this measure but unfortunately a good many of the hon. Members have not followed the provisions of this Bill. As I explained earlier when the original Act which this present Bill seeks to amend was brought forward, at that time it was meant to cover the entire country. It is not as if this Bill has now been brought here especially to extend this to the State of Jammu & Kashmir. After the original measure was passed, subsequently the legal opinion was that there was some doubt as to whether the original Act that we passed would also apply to Jammu & Kashmir and so to put matters beyond any doubt we are bringing this Bill now before the hon. House.

Lala Jagat Narain was asking me what we were doing for the last two years and what we have done under this Bill. He also wanted that 'unlawful activities' should be defined. If Lalaji had taken the trouble of studying the Bill he would have found that 'unlawful activities' as far as this Bill is concerned means activities in relation to secession. Actually when the original measure was brought before Parliament it included many other things also and it would have been much more useful to curb the activities of the extremist elements in political life and we would have been able to deal with Naxalites and other factions of that kind very effectively. But all the Opposition members combined at that time and prevailed upon the Government to whittle down the provisions and accordingly this is confined only to secessionist activities and nothing more. There was also apprehension at that time—and a good many Opposition Members voiced that apprehension—that the powers taken by the Government under that measure were likely to be used against political opponents. We had clarified then that that was neither our policy, nor had we ever done so, nor we shall ever do that in future. We are taking these powers only to deal with such elements in the country who preach secession and who plead for taking away a part of the country and giving it to somebody else. If there are activities of this kind only then the powers taken under this Bill will be used. In fact we had only one occasion when we used these powers and that was in relation to the Mizo National Front. When there was an armed insurrection the Mizo National Front was declared unlawful under this Act. We do not want to take cognisance of mere prattle. If an irresponsible person or some person irresponsibly says something here or there we do not want to rush about all over the country and catch hold of such people and prosecute them under this Act. But if we find a responsible person, a person who is able to translate what he is saying into action, preaching secession then serious note of it should be taken and action under this law should be taken. I think it would not be a proper attitude for the Government to catch hold of any Tom, Dick or Harry who might say some irresponsible things publicily and to prosecute them under this Act. That will not be in keeping either with our intention or our policy.

Mr. Shejwalkar was asking why we had left out Kashmir. As I explained earlier, Kashmir was not left out. It is only to remove any possible doubts about its applicability to Jammu & Kashmir that this amendment is being brought forward.

Shri Bhupesh Gupta as usual came back to the problem of what Shri Namboodiripad and Shri Gopalan had said. As a matter of fact that had nothing to do with this present Bill but still I may again say that there is a lot of difference in amending or changing the Constitution and smashing the bourgeois State. These are the words they have used. It is not by mere play of words that anybody can defend somebody or accuse somebody. The very tenor, the very tone of the statement taken as a whole indicates what their intentions are.

SHRI BHUPESH GUPTA : What is meant by smashing? Will the Post Office be smashed?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Smashing is very different from changing or amending. This is the small difference that I wanted to point out here. There is nothing else for me to add. The only thing that this Bill seeks to do is to put the applicability of this measure to the State of Jammu & Kashmir beyond doubt and therefore hope that the House will accept this measure and pass it

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is —

"That the Bill to amend the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Madam, I move :

"That the Bill be passed"

The question was proposed

SHRI M. P BHARGAVA . I am very happy that this Bill is being extended to the State of Jammu & Kashmir and I do hope it would be possible for the Government of India to make applicable more and more laws as they are passed by this House or the other House to the State of Jammu & Kashmir and very soon a day will come when there will be no exception mentioned in the Bills that it shall apply to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir. I do hope that stage will soon be reached and all Bills will be applicable to all the States in India

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं इस सबध में ज्यादा बात कहना नही चाहता हू । अगर माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे माननीय सदस्य श्री बरबोरा ने शुरू मे जो भाषण किया था उसका जवाब दे दिया होता तो मै इस समय कुछ नही बोलता । यह रेवरेंड रोचुगा पुदामते, इडो बर्मा पायनियर मिशन, पार्टनरशिप मिशन, इडिपेडेंट चर्च आफ इडिया, ये तमाम सस्थाओं के सेल्फ स्टाइल प्रेजीडेंट है । ये 1954 से अमेरिका मे रह रहे है और उनको अमेरिका से आने का पासपोर्ट मिला है और वे साल मे वहा से एक दो बार यहा चले आते है । मणिपुर में इन्होंने एक क्रिश्चियन कालेज खोला है जो कि चान्दपुर मे है और उसके ये प्रेजीडेन्ट है । इस कालेज को इन्होने दो वर्ष से बद कर रखा है । इसका कारण यह है कि ये टीचरों से कहते है कि तुम लोग अमेरिकन मिशन के मुताबिक चलो और वहा के टीचरों ने उनके कहने के मुताबिक चलने से इन्कार कर दिया है । वहा के टीचर कहते है कि हम इडिपेडेंट चर्च आफ इडिया के तरीके पर चलेगे और यही वजह है कि उन्होंने इस कालेज को बद कर दिया है । इतना ही नहीं उस इलाके में पर्चे बाटकर वहा के लोगों खासकर क्रिश्चियन लोगों को उभाडते है कि तुम्हे हिन्दुस्तान से अलग हो जाना चाहिये और हिन्दुस्तान मे नही रहना चाहिये ।

ऐसी हालत में मै चाहूगा कि सरकार देखे कि यह रेवरेड रोचुगा पुदामते इस अनलाफुल ऐक्टिविटी में आ सकते है या नही और अगर इस कानून के तहत आ सकते है तो इनपर कार्यवाही की जाय ।

श्री राजनारायण : महोदया, मुझ को केवल एक बात कहनी है कि अब भी यह सरकार जम्मू और काश्मीर को भारत के अन्य राज्यो के समकक्ष नही समझ रही है अगर यह विधेयक कानून की शकल में आ जाय तो भी क्योकि इसमे लिखा है :

"इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ",

फिर आगे इसमें यह लिखा है :

"परन्तु जम्मू-कश्मीर राज्य मे यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।"

[श्री राजनारायण]

यह बिल्कुल गलत बात है। सरकार को इच्छा आज भी जम्मू और काश्मीर को अलग रखने की है, वरना सरकार को यह कहना चाहिये था कि यह सम्पूर्ण भारत में जिस में जम्मू-काश्मीर भी शामिल है तुरन्त लागू होगा। 'परन्तु" लगा कर के इस सरकार ने अपनी कलुषित भावना को इस विधेयक में चित्रित किया है जो सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के लिये बहुत ही हानिकारक है। इस लिये मैं कहता हूं कि अगर सरकार इसको इस ढंग से न पास करे तो अच्छा है क्योंकि इस से देश को कोई फायदा नहीं होगा। यह सरकार डरती है, यह सरकार हिचकती है, इसी लिये यह लचरपचर करती है और सोचती है कि इससे काम बना लेंगे। लेकिन ससे काम नहीं बनेगा। मैं कहता हूं कि साफ बोलो और कहो कि जम्मू-काश्मीर हमारा है, हमारे देश के कानून वहां भी उसी तरह से लागू होंगे जैसे अन्य प्रांतों में लागू होते हैं और उसी दिन लागू होंगे। इस लिये यह जो प्राविज़ो इसमें रखा गया है, यह बिल्कुल गलत है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : महोदया, जो श्री भार्गव जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की, मैं उनसे सहमत हूं और मैं भी उन्हीं भावनाओं में सम्मिलित होना चाहता हूं।

श्री राजनारायण : ये सभी भावनाओं से सहमत हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो रेवती कान्त जी ने बात कही, उसके बारे में मैंने इस लिये कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और इस मामले में हमारा ध्यान है। यदि इसमें ज़रा भी कोई चीज़ देखी गई तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री राजनारायण जो अपनी आदत से लाचार हैं। वे ऐसी बातें जरूर कहेंगे जिन का जवाब पहले कई बार दिया जा चुका है। उनको यह मालूम होना चाहिये कि जो भी कानून बनाया जाता है उसमें इस तरह का कानूनी प्रावधान बराबर किया जाता है . . .

श्री राजनारायण : और किस में ऐसा है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : आप सुनिये तो सही।

श्री राजनारायण : मैं सुनूं क्या . . .

श्री विद्या चरण शुक्ल : पहले सुनिये, फिर पूछियेगा। जो कानून पास किये जाते हैं उनको एक अप्वाइंटेड डेट से नोटिफाई कर के लागू किया जाता है।

श्री राजनारायण : दोनों बातें लिखी जाती हैं। किसी किसी में ऐसा भी लिखा जाता है कि कानून पास होते ही लागू हो जायगा।

श्री विद्या चरण शुक्ल : जैसी जहां कानूनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वैसा किया जाता है। इसमें कोई लचरपचर की बात नहीं है। ये आप के दिमाग़ की बातें हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा किया जाता है। इसमें नीति का कोई सवाल नहीं है, यह कानूनी आवश्यकताओं का सवाल है। राजनारायण जी अपनी आदत के अनुसार ही चीज़ को लचरपचर देखते हैं और इसी लिये ऐसी बातें कहते हैं।

श्री महावीर प्रसाद भार्गव : उनका दिमाग ही लचरपचर हो गया है।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MOTION *RE.* STATEMENT ABOUT TWO MAJOR RAILWAY ACCIDENTS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we go on to the Motion in the name of Mr. Yadav.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : मैडम, अब इसमें क्या होगा। क्या आज पांच बजे के बाद भी सदन बैठेगा ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : It depends on the Members. If Members want to sit, we will sit.

AN HON. MEMBER : We will discuss this today and finish it.

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : आज यह मूव कर दें और फिर यह आगे कांटिन्यु करेगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN : All right, let Mr. Yadav move it.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं निम्न प्रस्ताव उपस्थित करता हूं :